सम्राट चौधरी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री ने छुए नीतीश कुमार के पैर

पटना, 15 अप्रैल. भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने बुधवार को बिहार में मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली.

मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार के पैर छुए. चौधरी बिहार के ऐसे 24वें व्यक्ति हैं, जिन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का

पीएम मोदी ने सीएम और डिप्टी सीएम को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सम्राट चौधरी एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि सम्राट चौधरी की ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी अनुभव बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

सम्राट चौधरी के पास गृह समेत 29 विभाग रहेंगे

सम्राट चौधरी के पास गृह समेत 29 विभाग रहेंगे। विजय चौधरी को 10 और बिजेंद्र यादव को 8 विभाग मिले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यही विभाग बाकी मंत्रियों में बंटेंगे। तब तक तीनों मंत्री ही इनकी जिम्मेदारी संभालेंगे.

मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी के 5 बड़े निर्देश

- दोगुनी गति से काम कर समस्याओं का तेजी से समाधान होगा.
- मुख्यमंत्री स्तर से नीचे स्तर तक कहीं कार्यों को लटकाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए.
- प्रखंड और थाने में आम जनता को सुविधा मिले और समय से समस्याओं का समाधान हो.
- बिहार को विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए एकजुट होकर अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ काम करें.

आप सांसद अशोक मित्तल के घर ईडी की छापेमारी

नई दिल्ली/जालंधर. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई पंजाब और हरियाणा सहित कई स्थानों पर एक साथ की गई, जिसमें जालंधर स्थित उनके आवास समेत कुल 8-9 ठिकानों को जांच के दायरे में लिया गया है। यह जांच लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े फंड मैनेजमेंट और वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताओं को लेकर की जा रही है। हालांकि, ईडी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अशोक मित्तल को हाल ही में राज्यसभा में डिप्टी लीडर नियुक्त किया गया था.

श्रमिकों के उग्र प्रदर्शन के बाद केंद्र ने मांगी रिपोर्ट

लखनऊ, 15 अप्रैल. उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के उग्र विरोध-प्रदर्शनों के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गई है. श्रम मंत्रालय के तहत मुख्य श्रम आयुक्त ने हालात की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.

अधिकारियों के अनुसार अचानक भड़की हड़तालों और हिंसक घटनाओं ने प्रशासन को भी चौंका दिया है.

दरअसल, विरोध की शुरुआत सात अप्रैल को हरियाणा के मानेसर औद्योगिक क्षेत्र से हुई, श्रमिकों ने वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य-शिफ्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. इसके बाद मंगलवार को नोएडा के सेक्टर-62 में भी श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा.

श्रमिक के व्यवहार की जिम्मेदारी एजेंसी की भी

गौतमबुद्धनगर. उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में औद्योगिक शांति बनाए रखने और शासन की गाइडलाइंस का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की आउटसोर्सिंग एजेंसियों और संविदाकारों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई .यह बैठक मंगलवार देर रात हुई. बैठक के बारे में जिलाधिकारी ने बुधवार को जानकारी साझा की.

समुद्री मार्ग सुरक्षित रहना जरूरी

मर्चेंट शिपिंग पर हमले नहीं होंगे बर्दाश्त : जयशंकर

टोक्यो/नई दिल्ली 15 अप्रैल. वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी चिंता स्पष्ट रूप से रखी है.

'एजेडईसी प्लस' बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे हमले न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करते हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजारों पर भी गंभीर असर डालते हैं.एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी की इस बैठक में ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं पर चर्चा हुई.

जयशंकर ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित और निर्बाध समुद्री परिवहन वैश्विक विकास के लिए बेहद जरूरी है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनावों का सामना कर रही है.भारत, एक बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहने पर दी धमकी

तेहरान, 15 अप्रैल. ईरान के केंद्रीय सैन्य कमान खतम अल-अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दल्लाही अलीआबादी ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका फारस की खाड़ी में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखता है और ईरान के वाणिज्यिक जहाजों एवं तेल टैंकरों के लिए असुरक्षा पैदा करता है.

ईरान लाल सागर के महत्वपूर्ण बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य को ब्लॉक कर देगा. ईरानी सरकारी मीडिया में जारी संदेश में अलीआबादी ने स्पष्ट किया कि ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और लाल सागर में किसी भी प्रकार के आयात या निर्यात को जारी रखने की अनुमति नहीं देंगी.. ईरान का बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य पर काफी प्रभाव है, जो लाल सागर का दक्षिणी प्रवेश द्वार और वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ईरान समर्थित यमन के हूतू विद्रोहियों का लाल सागर की सीमा से लगे एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण है, जिसका उपयोग वे जहाजों पर हमले और समुद्री डकैती के जरिए इस मार्ग को ठप करने के लिए कर सकते हैं। यह जलडमरूमध्य पश्चिमी एशिया से निर्यात होने वाले प्राकृतिक गैस और तेल उत्पादों के लिए एक अनिवार्य मार्ग है.

अठारह देशों ने लेबनान में युद्धविराम की अपील की

बेरुत. लेबनान में जारी जंग को रोकने के लिए कनाडा-ब्रिटेन समेत 10 देशों की शुरू की गई शांति पहल अब बड़े वैश्विक अभियान में बदलती नजर आ रही है. साझा बयान का समर्थन करते हुए यूरोप के आठ अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए हैं. इससे अब कुल 18 देशों ने एक सुर में लेबनान में तत्काल युद्धविराम की अपील की है. इन देशों ने बढ़ते मानवीय संकट और विस्थापन पर गहरी चिंता जताते हुए स्पष्ट किया है कि क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए लेबनान को कूटनीतिक वार्ताओं का हिस्सा बनाना अनिवार्य है. बयान में मार्च में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के तीन शांति रक्षकों की हत्या की भी निंदा की गई है. संयुक्त राष्ट्र ने पिछले हफ्ते तीन इंडोनेशियाई शांति रक्षकों की मौत की शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की थी. इसमें पाया कि ये दो हमले संभवतः इजरायली टैंक के गोले और एक आईईडी के कारण हुए थे. मुमकिन है कि वह हिजबुल्ला ने लगाया हो. संयुक्त बयान में कहा गया, हम ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, साइप्रस, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, आइसलैंड, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री, क्षेत्रीय तनाव कम करने के प्रयासों में लेबनान को शामिल करने का आह्वान करते हैं और सभी पक्षों से एक स्थायी राजनीतिक समाधान की दिशा में काम करने का आग्रह करते हैं.

बैसाखी से लौट रही बस पलटी आठ श्रद्धालुओं की मौत

फतेहगढ़ साहिब, 15 अप्रैल. पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में बैसाखी पर्व से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से बड़ा हादसा हो गया.

बैसाखी के अवसर पर आनंदपुर साहिब से लौट रही संगत की बस भटेड़ी गांव के पास पलट गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए. हादसा देर रात हुआ, जब बस अपने गंतव्य की ओर लौट रही थी. अचानक हुए इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे.

गोदाम में आग लगने से 3 लोगों की मौत

नई दिल्ली. बाहरी दिल्ली के बुध विहार इलाके में प्लास्टिक अपशिष्ट गोदाम में भीषण आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई. यह जानकारी अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को दी. प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित एक ऐसे परिवार के सदस्य थे जो बुध विहार के मांगे राम पार्क इलाके में स्थित गोदाम में बनी एक अस्थायी झोपड़ी में रहते थे.

पवन खेड़ा अग्रीम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट से झटका

नयी दिल्ली 15 अप्रैल. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी.यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा की एक शिकायत से संबंधित है। न्यायालय का यह आदेश असम पुलिस की एक अपील पर आया है। उच्च न्यायालय के पास इस मामले में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है. न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि खेड़ा असम की उचित अदालत से राहत मांगने के लिए स्वतंत्र हैं। पीठ ने कहा कि अगर खेड़ा असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का उस आवेदन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह पूरा मामला गत पांच अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खेड़ा के लगाए उन आरोपों से जुड़ा है.

3 दिवसीय सत्र से पहले विपक्ष की बड़ी बैठक

खरगे आवास पर हुई बैठक में राहुल भी शामिल

परिसीमन और आरक्षण मुद्दे पर गहन मंथन

नई दिल्ली, 15 अप्रैल. सांसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण तथा संसदीय सीटों के विस्तार के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए संसद की कल से शुरू हो रही तीन दिवसीय बैठक से पहले बुधवार को यहां विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई जिसमें संसद में सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया.

कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के यहां स्थित आवास 10 राजाजी मार्ग पर हुई इस बैठक में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया. बैठक में विपक्षी नेताओं ने महिला आरक्षण विधेयक और संसदीय सीटों के विस्तार को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया. बैठक को लेकर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया संसद के कल से हो रहे विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के यहां स्थित आवास पर विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में भाग लिया.

वीडियो संदेश से ममता पर साधा निशाना : शाह

मौसम के कारण रैली में नहीं पहुंच पाये शाह

कोलकाता, 15 अप्रैल. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लंबे समय से चले आ रहे गोरखा मुद्दे के स्थायी समाधान का बुधवार को आश्वासन दिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला.

शाह खराब मौसम के कारण रैली स्थल पर नहीं पहुंच सके और वीडियो संदेश के माध्यम से उत्तर बंगाल के पर्वतीय इलाके के लोगों को संबोधित किया. वह दार्जीलिंग में निर्धारित चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए वहां नहीं पहुंच सके थे, इसलिए उन्होंने मालदा से एक वीडियो संदेश के जरिए पहाड़ी क्षेत्र के मतदाताओं से संवाद किया.

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव

शाह को दार्जीलिंग और कुर्सियोंग विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में दार्जीलिंग के लेबोंग में अपनी पहली रैली को संबोधित करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण बागडोगरा हवाई अड्डे पर उनके विमान को उतरने की अनुमति मिल सकी. उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने पूरे दार्जीलिंग में पुलिस राज स्थापित कर दिया है. सुश्री बनर्जी की सरकार पर्वतीय इलाकों में जिस तरह का पुलिस शासन चला रही है, भाजपा के सत्ता में आते ही उसे उखाड़ फेंका जाएगा और गोरखाओं के साथ हुए अन्याय को समाप्त किया जाएगा. गोरखा मुद्दा अब तक अनसुलझा रहने का कारण बताते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री पर इसकी अनदेखी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में उन्होंने पहाड़ी मुद्दों पर तीन बार बैठकें बुलाईं, लेकिन सुश्री बनर्जी न तो खुद शामिल हुईं और न ही उन्होंने दिल्ली में अपना कोई प्रतिनिधि भेजा. उन्होंने कहा कि उनके पश्चिम बंगाल दौरों के दौरान भी चर्चा के प्रयास सफल नहीं हुए, राज्य सरकार ने इसके लिए समय नहीं दिया. शाह ने आरोप लगाया कि सुश्री बनर्जी पर्वतीय इलाकों में शांति या गोरखा समुदाय के लिए संवैधानिक अधिकारों की बहाली नहीं चाहतीं. मतदाताओं को आश्वस्त करते हुए 5 मई को बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद उनका पहला काम गोरखाओं के लंबे समय से लंबित मुद्दों का स्थायी समाधान खोजना होगा.

उदयनिधि स्टालिन की घोषित संपत्तियों के खिलाफ याचिका

उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग से मांगा जवाब

चेन्नई, 15 अप्रैल. मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को आयकर महानिदेशक (जांच) और केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा 2021 और 2026 के चुनावी हलफनामों में घोषित संपत्तियों में कथित महत्वपूर्ण विसंगतियों की जांच की मांग करने वाली रिट याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. न्यायालय ने चेपॉक-ट्रिप्लिकेन विधानसभा क्षेत्र के निवासी आर. कुमारवेल (56) द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की, जहां से द्रमुक युवा मोर्चा के सचिव और मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन के पुत्र उदयनिधि लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं. मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की प्रथम पीठ ने सूचना एवं आयकर विभाग के महानिदेशक और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय की. सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि अगर कोई झूठा हलफनामा साबित होता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी. न्यायालय से कहा गया कि चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका दायर करनी चाहिए. दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने आयकर महानिदेशक और केंद्रीय कार्पोरेट मंत्रालय को निर्देश जारी करते हुए मामले को आगामी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया. कुमारवेल ने मंगलवार को दायर की गयी अपनी याचिका में कहा कि उदयनिधि द्वारा 2021 और 2026 के दौरान दायर किये गये चुनावी हलफनामों के तुलनात्मक विश्लेषण से पहले घोषित संपत्तियों का गायब होना, ऋणों में अस्पष्ट भिन्नता, वित्तीय लेनदेन का गलत विवरण और हलफनामे में दिए गए खुलासे और कंपनी के दस्तावेजों के बीच विरोधाभास का पता चलता है. 7.36 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की थी.

पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनावों के पहले चरण में केंद्रीय बलों की भारी तैनाती

कोलकाता, 15 अप्रैल. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों में फैले 152 निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की 2,407 कंपनियों की तैनाती की घोषणा की है, जहां मतदान 23 अप्रैल को होना है. प्रत्येक कंपनी में लगभग 100 जवान शामिल हैं. राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा दिये गये आश्वासन के बाद व्यापक तैनाती की घोषणा की गई है. पहले चरण में उत्तरी बंगाल के सभी जिलों दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा सहित एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र शामिल हैं. झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुरा सहित जंगलमहल क्षेत्र में भी मतदान होगा. बीरभूम और मुर्शिदाबाद जैसे महत्वपूर्ण जिले भी इस चरण में शामिल हैं. इसके अलावा, पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर के कुछ हिस्सों के साथ-साथ पश्चिमी बर्दवान में भी पहले चरण में मतदान होने वाला है. सभी जिलों में से मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की सबसे अधिक तैनाती होगी.

पश्चिम बंगाल में हर महिला को हर महीने 3000 रुपये देने का वादा : भाजपा

कोलकाता. भारतीय जनता पार्टी (भारतीय जनता पार्टी) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए मातृशक्ति भरोसा कार्ड योजना का अनावरण करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से पार्टी का लक्ष्य राज्य की प्रत्येक महिला को 3000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्मृति ईरानी ने कोलकाता में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न क्षेत्रों से आई पांच महिलाओं को प्रतीकात्मक तौर पर यह कार्ड सौंपा. इस अवसर पर उनके साथ भवानीपुर और नंदीग्राम से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी और सोनारपुर दक्षिण से उम्मीदवार रूपा गांगुली भी मौजूद थीं।यह योजना भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र संकल्प पत्र का एक प्रमुख हिस्सा है। मीडिया को संबोधित करते हुए ईरानी ने कहा कि यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के प्रति पार्टी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए आर्थिक सुरक्षा मौलिक है और यह पहल ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं तक पहुंचेगी.

राउज एवेन्यू अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा और 8 अन्य को समन जारी किया

नई दिल्ली, 15 अप्रैल. हरियाणा में गुरुग्राम के शिकोहपुर भूमि घोटाले मामले में यहां की राउज एवेन्यू कोर्ट ने श्री रॉबर्ट वाड्रा और आठ अन्य व्यक्तियों को समन जारी किया है.

विशेष न्यायाधीश सुशांत चांगोत्रा ने इस हाई-प्रोफाइल धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा सहित सभी आरोपियों को 16 मई को पेश होने का निर्देश दिया है।यह मामला 2008 के एक भूमि सौदे से संबंधित है, जिसमें श्री रॉबर्ट वाड्रा के स्वामित्व वाली कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज से शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ईडी की जांच इन आरोपों पर केंद्रित है कि हुड्डा प्रशासन न वाड्रा की कंपनी को कमर्शियल लाइसेंस प्रदान कर भारी वित्तीय लाभ पहुंचाया, जिससे जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गयी.

पूर्व राष्ट्रपति ने किया महिला आरक्षण का समर्थन

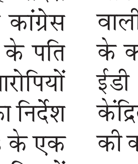

नई दिल्ली, 15 अप्रैल. भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर अपनी मजबूत आवाज उठाई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के लिए आभार जताया और इसे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया. पाटिल ने इस पहल को सिर्फ एक संवैधानिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में बड़े परिवर्तन की शुरुआत बताया है. अपने पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं को सशक्त बनाने का असली रास्ता उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर भागीदारी देना है. संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति न केवल बेहतर नीति निर्माण को बढ़ावा देगी, बल्कि समाज में संतुलित और संवेदनशील नेतृत्व भी सुनिश्चित करेगी. यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर बहस तेज है. पाटिल का यह समर्थन न केवल सरकार के प्रयासों को मजबूती देता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है.अपने पत्र में पाटिल ने लिखा कि यह संवैधानिक संशोधन महिलाओं को राजनीतिक और कानूनी संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देने का मार्ग प्रशस्त करेगा.

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

कनिष्ठ अभियंता (सिविल/इलैक्ट्रिकल) की भर्ती – 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक, अपने विभिन्न कार्यालयों में कनिष्ठ अभियंता (सिविल/इलैक्ट्रिकल) के 11 पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इस पद के लिए चयन देशव्यापी केंद्र-वार ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा और भाषा दक्षता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। सम्पूर्ण विज्ञापन बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर अप्रैल 2026 के तीसरे सप्ताह में उपलब्ध होगा और इसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ / रोज़गार समाचार में भी प्रकाशित किया जा रहा है। आवेदन पत्र बैंक की वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

महत्वपूर्ण तारीखें:

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अवधि	16 अप्रैल 2026 - 06 मई 2026
ऑनलाइन परीक्षा की तारीख (अनंतिम)	06 जून 2026

"पैसे का वादा करने वाले ई-मेल / एसएमएस / टेलीफोन द्वारा धोखा न खाएं"

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम मर्या.
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल-462003
फोन : +91-755-4027100, 2774340, 42, Website : mpstdc.com
क्रमांक : 159/यांत्रिकी/पविनि/26 दिनांक : 15.04.2026

निविदा सूचना 141/2026_STDC_500622_1

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा प्रपत्र APPENDIX 2.10 पर म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है। **कार्य का नामः- बैढ़न, जिला सिंगरौली में 10 बेडिड आयुष हॉस्पिटल का निर्माण कार्य, आंतरिक विद्युतीकरण सहित। (14 माह) कार्य की लागत राशि रुपये 477.41 लाख।**
वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से क्रय किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की **अंतिम तिथि 06.05.2026 समय सायं 05:00 बजे तक** निर्धारित है। कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।
म.प्र. माध्यम/125339/2026 **कार्यपालन यंत्री**

M.P. HOUSING & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD

Online percentage rate bids for the following works are invited from Registered Contractors and Reputed firm full filling registration criteria :-

S. No.	System Tender No.	Name of Work	PAC (Rs. In Lakh)	EMD (in Rs.)	Cost of Bid Document Including GST (in Rs.)	Completion Period
1.	2026_MPHID_498188	Construction of Degree College with Development works at Nagod Distt. Satna.	Rs. 764.99	765000/-	23600.00	15 (Fifteen) Months I/C Rainy Season.

Note :- (1) Full details of the above tenders can be seen on **http://www.mptenders.gov.in.** Amendments to NIT, if any, would be published on website only. (2) Cost of Tender form will be paid online Tender portal. (3) Tender will be purchased from 16.04.2026, 02.00 Hrs. and last date of Purchase & Submission **08.05.2026, 05.00 Hrs.** (4) Tender will be Opened at 11.05.2026, 1.00 Hrs.

(Manoj Kumar Dwivedi)
E.E., Div. Satna
Mob. : 9131194716

Visit us : www.mphousing.in
E-mail : eednhbstn@mp.gov.in
M.P. Madhyam/125333/2026
f / mphidb
X / mphidb